



भारत में बैलेस्टिक मिसाइलों का... पेज 5



यूट कीड़ा के दोष..... पेज 7

मुकाबले के चक्कर में आदमी का जीवन एक कारखाने के समान हो गया है, आदमी का सबसे विश्वसनीय अवतार

वर्ष 6, अंक 332

भोपाल, गुरुवार 14 मई, 2026

ज्योष्ठ कृष्ण पक्ष, द्वादशी 2083

मूल्य 2 रुपए

## रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार! 800 ड्रोनों से बरसायी आग, लोग जिंदा जले



दैनिक कारखाने का सफर। एजेंसी नई दिल्ली

एक तरफ जहां वैश्विक स्तर पर रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति वार्ताओं की चर्चाएं तेज हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के मैदान में रूस ने अब तक का सबसे भीषण हमला बोल दिया है। बुधवार को रूस ने यूक्रेन के विभिन्न शहरों पर 800 ड्रोन दागे, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने इस हमले को पिछले 4 वर्षों में मॉस्को द्वारा किया गया "सबसे लंबा और बड़ा हमला" करार दिया है। जेलेन्स्की ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर बताया कि यह हमला सुबह के समय शुरू हुआ और राजधानी कीव, पोलैंड के पास पश्चिमी शहर ल्वीव, और काला सागर पर स्थित बंदरगाह शहर ओडेसा, तथा अन्य आबादी वाले इलाकों में घंटों तक जारी रहा। जैसे-जैसे बमबारी दोपहर तक खिंची गई, जेलेन्स्की ने कहा, "हमारे सैनिक यूक्रेन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन रूस का साफ मकसद हमारी हवाई सुरक्षा प्रणाली पर इतना ज्यादा दबाव डालना है कि वह उसे संभाल न पाए।" उन्होंने चेतावनी दी कि ड्रोन हमलों की इस बौछार के बाद कूज और

बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यह "यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए सबसे लंबे और बड़े हमलों में से एक था।" इस हमले से पड़ोसी देश भी सहम गए। हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार ने कहा कि उनकी नई सरकार ने हंगरी की सीमा के पास हुए ड्रोन हमले को लेकर रूसी राजदूत को तलब किया है; यह कदम उनके पूर्ववर्ती विक्टर ओबन के मॉस्को के साथ दोस्ताना संबंधों की तुलना में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मैग्यार ने पत्रकारों से कहा, "हंगरी की सरकार ट्रांसकारपैथिया पर रूस के हमले की कड़ी निंदा करती है।" उन्होंने आगे कहा कि विदेश मंत्री अनोता ओबन गुरुवार सुबह रूसी राजदूत से बात करेंगी। मैग्यार ने बताया कि विदेश मंत्री रूसी राजदूत से पूछेंगी कि "रूस और वोलादिमिर पुतिन आखिरकार इस खूनी युद्ध को कब खत्म करने की योजना बना रहे हैं।" मैग्यार की इन टिप्पणियों के बाद जेलेन्स्की ने 'X' (ट्विटर) पर लिखा, "आपकी सहानुभूति और मजबूत रुख के लिए आपका धन्यवाद!" शहर के अधिकारियों ने बताया कि कीव के ओबोलोन्स्की जिले में एक खुले इलाके में ड्रोन का मलबा पड़ा, जिससे किसी को कोई चोट नहीं आई; उस समय

राजधानी के ऊपर हवाई सुरक्षा प्रणालियाँ रूसी ड्रोनों का मुकाबला कर रही थीं। मेयर विटाली क्लित्स्को ने बताया कि आपातकालीन सेवाएँ घटनास्थल पर पहुंच गई थीं। बुधवार को इससे पहले पूरे शहर में धमाकों की आवाजें सुनी गई थीं। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेक्जेंडर कोवल के अनुसार, कीव के पश्चिम में स्थित रिचने क्षेत्र में हुए एक ड्रोन हमले में तीन लोगों की मौत हो गई। मॉस्को के हमले लगातार जारी हैं, भले ही यूक्रेन अपनी हालिया सैन्य सफलताओं से उत्साहित है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने - बिना कोई सबूत दिए - कहा है कि युद्ध अब खत्म होने के करीब हो सकता है। मंगलवार को जेलेन्स्की ने बताया कि यूक्रेन के 14 इलाकों पर हमले हुए, जिसके बाद रात भर यूक्रेन के रिहायशी, ऊर्जा और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रहे। जेलेन्स्की ने कहा, "यूक्रेन का समर्थन करना और रूस के इस युद्ध पर चुप न रहना जरूरी है। जब भी युद्ध खबरों की सुर्खियों से हटता है, तो इससे रूस को और भी ज्यादा क्रूर बनने का बढ़ावा मिलता है।" जेलेन्स्की का इरादा शांति इस बात की ओर था कि दुनिया का ध्यान इस समय ईरान युद्ध पर केंद्रित है।

## युद्ध संकट पर आरबीआई गवर्नर का अलर्ट, लंबा रिचिंगा तो बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम!

दैनिक कारखाने का सफर। एजेंसी नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि अगर पश्चिम एशिया संकट लंबे समय तक जारी रहता है, तो सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं। मल्होत्रा ने स्विट्जरलैंड में मंगलवार को एक



व्यवधानों का असर भारत पर पड़ना शुरू हो गया है। आरबीआई गवर्नर ने संकट का जिक्र करते हुए कहा कि अगर यह लंबे समय

तक जारी रहता है तो "सरकार वास्तव में इन मूल्य वृद्धि का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं पर डाल सकती है। यह सिर्फ समय की बात है।" सरकार ने 28 फरवरी को शुरू हुए पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद

पेट्रोल और डीजल की खुरदरा कीमतों में वृद्धि नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन के विकल्पों का उपयोग, सोने की खरीद और विदेश यात्रा को स्थगित करने जैसे उपायों का आह्वान किया है। रुपये में भारी गिरावट आई है और वर्तमान में यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के नीचे पहुंच गया है।

## मी लॉर्ड! आपने जो बोला वो आदेश में तो नहीं लिखा... सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर लगाया जुर्माना



दैनिक कारखाने का सफर। एजेंसी नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कच्छ के बहुचर्चित गोंधर (चरागाह) भूमि विवाद में एक अहम फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई है। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि खुली अदालत में जजों द्वारा बोला गया मौखिक आदेश और बाद में जारी किए गए अंतिम लिखित आदेश में बड़ा अंतर है। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि यह बदलाव अडानी पोर्ट्स को फायदा पहुंचाने वाला है। अदालत ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे 'कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग' और 'अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने' का प्रयास बताया। साथ ही, याचिकाकर्ताओं पर 2,000-2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकार को सभी पक्षों को सुनने के बाद नया आदेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। जस्टिस माहेश्वरी की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों को नामंजूर करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत का साइन किया हुआ आदेश ही अंतिम होता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा: हस्ताक्षरित आदेश ही अदालत की 'अंतिम और अपरिवर्तनीय राय' है। अदालत में लिखवाए जाने के बाद कई दौर के सुधार के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट मास्टर को जो आदेश लिखवाया जाता है, वह केवल एक 'रफ ड्राफ्ट' या 'ढांचा' होता है। चेंबर में साइन करने से पहले इसे सुधार और बेहतर किया जाता है। पीठ ने यूट्यूब वीडियो, मीडिया रिपोर्ट्स और स्टॉक एक्सचेंज डिस्कलोजर का हवाला देने पर भी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक अधूरे यूट्यूब वीडियो पर भरोसा कर रहे हैं। लिखित आदेश में कोई 'बड़ा बदलाव' नहीं किया गया है, यह केवल डिक्लेरेशन को सुधारने की प्रक्रिया थी। अदालत के कामकाज को 'व्यावहारिक वास्तविकताओं' का जिक्र करते हुए बेंच ने बताया कि जिस दिन इस अपील पर सुनवाई हुई थी, उस दिन उनके सामने 71 मामले लगे हुए थे। संवैधानिक अदालतों पर काम का भारी बोझ होता है। जज अदालत के समय का सही इस्तेमाल करने के लिए ओपन कोर्ट में एक छोटा ड्राफ्ट आदेश लिखवाते हैं और बाद में चेंबर में उसे बेहतर करके साइन करते हैं। इससे समय की बचत होती है और एक दिन में ज्यादा मामलों की सुनवाई की जा सकती है।

## बीजिंग पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जोरदार स्वागत जिनपिंग ने बढ़ाया दोस्ती का साथ, 'चीन-अमेरिका प्रतिद्वंद्वी नहीं, सहयोगी बनें'

दैनिक कारखाने का सफर। एजेंसी बीजिंग

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में कहा है कि अमेरिका और चीन को एक-दूसरे का विरोधी होने के बजाय साझेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के एक-दूसरे की सफलता में योगदान देना चाहिए और मिलकर तरक्की का रास्ता चुनना चाहिए। जिनपिंग ने वैश्विक चुनौतियों पर अमेरिका-चीन के मिलकर काम करने पर जोर दिया है। जिनपिंग का यह बयान ऐसे समय आया है, जब वार्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में हैं। शी जिनपिंग ने अमेरिका और चीन में दोस्ती की बात कही है तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी तारीफ की है। ट्रंप ने बीजिंग में शी को महान नेता बताते हुए कहा कि आपका दोस्त होना मेरे लिए गर्व की बात है। ट्रंप ने चीन और अमेरिका के बीच के रिश्ते पहले से बेहतर होने की उम्मीद जताई। बीजिंग में हुए शानदार स्वागतसे भी ट्रंप खुश दिखे हैं। शी जिनपिंग बोले- दुनिया एक नए मोड़ पर है। चीन और अमेरिका को संबंधों का नया मॉडल बनाना होगा। सवाल यह है करि क्या हम वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना कर दुनिया को ज्यादा स्थिरता दे सकते हैं? शी जिनपिंग ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि चीन और अमेरिका की सफलता को एक-दूसरे के लिए एक अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए। चीन-अमेरिका के स्थिर संबंध दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। शी ने कहा कि दोनों देशों को



"साझेदार के तौर पर काम करना चाहिए। जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों की व्यापारिक टीमों ने कुल मिलाकर संतुलित और सकारात्मक तरीके हासिल किए हैं। चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात के दौरान कहा कि

व्यापार युद्ध में कोई विजेता नहीं होता है। इसे हार और जीत की तरह से नहीं देखा चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा- अमेरिका और चीन को एक-दूसरे का विरोधी होने के बजाय साझेदार होना चाहिए। दोनों मुल्कों को एक-दूसरे की सफलता में योगदान देना चाहिए और मिलकर

समृद्ध होना चाहिए। हम वैश्विक चुनौतियों से लड़ने पर ध्यान देना होगा। चीन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शुरुआती संबोधन में शी जिनपिंग से मुलाकात को सम्मान की बात बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। जब भी कोई मुश्किल आई तो हमने उसे मिलकर सुलाझाया। मैं जिनपिंग को फोन करता था और वह मुझे फोन करते थे। हमने परेशानियों पर मिलकर काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि मैं हर किसी से कहता हूँ कि आप (जिनपिंग) एक महान नेता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन में सबसे बेहतरीन कारोबारी नेताओं को अपने साथ लेकर आए हैं। मैं कह सकता हूँ कि आपके साथ होना सम्मान की बात है और आपका दोस्त होना भी सम्मान की बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। चीन के ग्रेट हॉल में गुरुवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैनिकों ने कोरियोग्राफड मिलिट्री शो का प्रदर्शन किया। ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रेसिडेंट जिनपिंग अपने डेलिगेशन के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप और जिनपिंग आखिरी बार अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में एक एपीईसी सफ्टवॉर के दौरान मिले थे। वहीं चीन दौरे की बात की जाए तो अमेरिका राष्ट्रपति कई साल बाद बीजिंग गए हैं।

## इजराइल और यूएई के बीच बंद कमरे में हुई सीक्रेट डील!

दैनिक कारखाने का सफर। एजेंसी नई दिल्ली

मध्य पूर्व (West Asia) की राजनीति में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने दावा किया कि युद्ध के चरम के दौरान उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की एक अत्यंत गोपनीय यात्रा की थी। हालांकि, अबु धाबी ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे "पुरी तरह बेबुनियाद" करार दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 26 मार्च को, जब क्षेत्र में ईरान के साथ संघर्ष (ऑपरेशन रोसिंग लायन) अपने चरम पर था, नेतन्याहू ने गुप्त रूप से अमीराती शहर अल ऐन का दौरा किया। X पर जारी एक बयान में, नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि इजराइली नेता ने 26 मार्च को, जब पश्चिम एशिया में युद्ध अपने चरम पर था, अमीराती शहर अल ऐन में शेख मोहम्मद बिन जायेद (जिन्हें आम तौर पर MBZ के नाम से जाना जाता है) से मुलाकात की थी। इजराइली बयान के अनुसार, यह बातचीत कई घंटों तक चली और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल और UAE के संबंधों में एक "ऐतिहासिक सफलता" साबित हुई। बयान में कहा गया कि चर्चा का मुख्य विषय युद्ध के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग और रणनीतिक तालमेल था। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा, "ऑपरेशन रोसिंग लायन के दौरान, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुप्त रूप से संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया, जहाँ उन्होंने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद से मुलाकात की। इस दौरे से इजराइल और UAE के संबंधों में एक ऐतिहासिक सफलता मिली है।" इस दावे पर UAE के विदेश मंत्रालय ने तुरंत पलटवार किया। मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर



उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि नेतन्याहू ने देश का दौरा किया था या UAE में किसी इजराइली सैन्य प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया था। मंत्रालय ने कहा, "संयुक्त अरब अमीरात उन रिपोर्टों को खारिज करता है जिनमें इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के UAE के कथित दौरे या देश में किसी इजराइली सैन्य प्रतिनिधिमंडल के स्वागत की बात कही गई है।" UAE ने इस बात पर भी जोर दिया कि इजराइल के साथ उसके संबंध 2020 में हस्ताक्षरित 'अब्राहम समझौते' के तहत खुले तौर पर संचालित होते हैं—जिसने दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाया था—न कि किसी गुप्त समझौते के जरिए। बयान में कहा गया, "बिना किसी घोषणा के किए गए दौरे या गुप्त समझौते के बारे में किए गए कोई भी दावे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, जब तक कि UAE के संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी आधिकारिक घोषणा न की जाए।" ये पूरी तरह से विरोधाभासी बयान

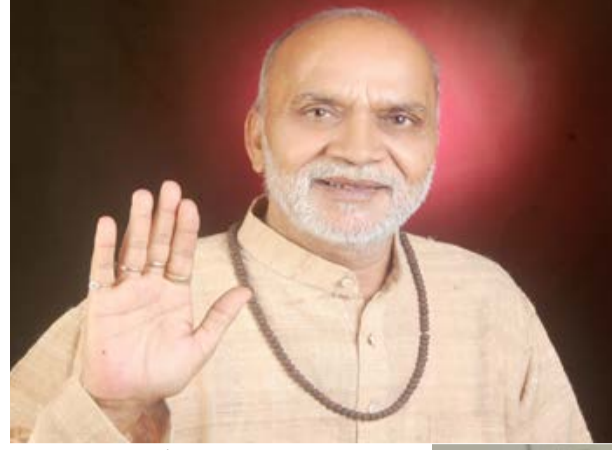
ऐसे समय में सामने आए हैं, जब ईरान के साथ टकराव के दौरान इजराइल और UAE के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग की खबरें आ रही हैं। इस टकराव के दौरान पूरे क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले देखने को मिले थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार—जिसने इस मामले से परिचित एक सूत्र का हवाला दिया है—मोसाद के प्रमुख डेडी बारनिया ने संघर्ष के दौरान कम से कम दो बार UAE का दौरा किया था, ताकि दोनों देशों के बीच सैन्य मामलों में तालमेल बिठाया जा सके। 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने भी इससे पहले बारनिया के इन दौरों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस बीच, इजरायल ने अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने इस हफ्ते कहा कि इजरायल ने ईरान के साथ युद्ध के दौरान, अमीरात के अनुरोध पर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में सैन्य कर्मियों के साथ एक 'आयरन डोम' बैटरी तैनात की थी। यह इजरायल की प्रमुख हवाई रक्षा प्रणाली की पहली विदेशी तैनाती थी। यह तैनाती संघर्ष के शुरुआती चरण में, UAE के राष्ट्रपति और नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत के बाद की गई थी। अमेरिका-इजरायल की सैन्य कार्रवाई के बाद, ईरान ने UAE सहित कई खाड़ी देशों पर जवाबी हमले किए थे। रिपोर्टों से पता चला कि कुछ हमलों में इस क्षेत्र के नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया था। हालांकि, 2020 में 'अब्राहम समझौते' के जरिए संबंधों के सामान्य होने के बाद से, UAE और इजरायल ने हाल के वर्षों में आर्थिक और सुरक्षा सहयोग का निरंतर किया है, लेकिन अबु धाबी ने इस क्षेत्र में इजरायल के सैन्य अभियानों के कुछ पहलुओं से खुद को सार्वजनिक रूप से अलग रखने की भी कोशिश की है - खासकर गाजा युद्ध और ईरान के साथ व्यापक टकराव को लेकर क्षेत्र में बढ़ते तनाव और घरेलू संवेदनशीलता के बीच।

# गतांक से आगे : लोक कल्याण हेतु दादाजी का अवतरण



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

परम पूज्य सद्गुरु श्री दादाजी गुरुदेव के जीवन से जुड़ी अनेक दिव्य एवं प्रेरणादायी घटनाएँ भक्तों के हृदय में अटूट श्रद्धा और विश्वास का संचार करती हैं। उनके श्रीचरणों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक अनुभूति, आत्मबल और ईश्वरीय कृपा का अनुभव करता था। दादाजी गुरुदेव केवल एक संत नहीं, बल्कि लोककल्याण के लिए अवतरित दिव्य चेतना थे, जिनकी कृपा से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी सहज रूप से पूर्ण हो जाते थे। शिवाजी नगर साढ़े छः नंबर क्षेत्र में दादाजी गुरुदेव के सानिध्य में अनेक चमत्कारिक घटनाएँ घटित हुईं। इन प्रसंगों ने सामान्य जनमानस के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले भक्तों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी गहराई से प्रभावित किया। दादाजी के श्रीमुख से निकला प्रत्येक वचन सत्य सिद्ध होता था। उनके आशीर्वाद में अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान थी। ऐसा ही एक प्रेरणादायी प्रसंग जबलपुर निवासी हरeram बाबा के पुत्र से जुड़ा हुआ है, जो हॉकी का प्रतिभाशाली खिलाड़ी था और गोलकीपर के रूप में खेलता था। वह राज्य स्तरीय टीम में चयन पाने के लिए निरंतर परिश्रम कर रहा था, किन्तु एक बार उसका चयन राज्य स्तरीय टीम में नहीं हो पाया। इस घटना से वह और उसका परिवार अत्यंत निराश हो गया। हरeram बाबा अत्यंत व्यथित होकर दादाजी गुरुदेव के श्रीचरणों में पहुँचे और विनम्र भाव से निवेदन किया कि उनके पुत्र का चयन राज्य स्तरीय हॉकी टीम में नहीं हुआ है। दादाजी ने सहज मुस्कान के साथ कहा यदि राज्य स्तरीय टीम में चयन नहीं हुआ, तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर खेला देंगे। दादाजी के इन दिव्य वचनों को सुनकर हरeram बाबा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विनम्रता से कहा कि जब राज्य स्तरीय टीम में ही चयन नहीं हुआ,



तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे संभव होगा। तब दादाजी ने अत्यंत आत्मविश्वास और करुणा से कहा "वह अवश्य खेलेगा।" समय बीतने के साथ दादाजी गुरुदेव के वचन अक्षरशः सत्य सिद्ध हुए। दादाजी की कृपा से उस खिलाड़ी का चयन सीधे राष्ट्रीय स्तर की हॉकी टीम में हो गया। यह घटना परिवार ही नहीं, बल्कि सभी श्रद्धालुओं के लिए आश्चर्य और आस्था का अद्भुत उदाहरण बन गई। जिस खिलाड़ी का नाम राज्य स्तरीय सूची में भी नहीं आया था, वह राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने पहुँचा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान प्रारंभिक मैचों में विरोधी टीम ने 2 गोल कर दिए, जिससे खिलाड़ी निराश हो गया। बाद में हरeram बाबा ने दादाजी से इस विषय में निवेदन किया कि उनका पुत्र गोल नहीं रोक पाया। तब दादाजी ने अत्यंत सरल किंतु गूढ़ भाव से कहा "तुमने उसे खेलने के लिए कहा था, विजय दिलाने के लिए नहीं। हमने उसे राष्ट्रीय स्तर पर खेला दिया, जैसा तुमने निवेदन किया था।" दादाजी गुरुदेव के इन वचनों ने हरeram बाबा को भीतर तक भावविभोर कर दिया। उन्हें अनुभव



हुआ कि दादाजी की कृपा और संकल्प शक्ति के सामने सांसारिक सीमाएँ कोई महत्व नहीं रखतीं। यह प्रसंग केवल एक खेल प्रतियोगिता की घटना नहीं, बल्कि सद्गुरु की दिव्य शक्ति, कृपा और भक्तों के प्रति उनके असीम प्रेम का सजीव प्रमाण है। दादाजी गुरुदेव अपने भक्तों को यह संदेश देते थे कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और समर्पण

से जीवन की कठिन से कठिन बाधाएँ भी दूर हो सकती हैं। सद्गुरु की कृपा जिस साधक पर होती है, उसके जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता का मार्ग स्वयं खुलने लगता है। दादाजी गुरुदेव की दिव्य कृपा समस्त भक्तों पर सदैव बनी रहे। जय श्री दादाजी गुरुदेव

## सीबीएसई 12वीं रिजल्ट- सरकारी स्कूलों का दबदबा, छात्राओं ने मारी बाजी



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 12वीं परीक्षा 2026 के नतीजों ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा की वास्तविक तस्वीर सामने ला दी है। जहाँ सरकारी मॉडल पर संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) और केंद्रीय विद्यालय (KV) ने शानदार परिणाम देकर बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था की ताकत दिखाई, वहीं सबसे ज्यादा छात्रों वाले निजी, यानी इंटरनेट स्कूलों का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा। खास बात यह है कि इन निजी स्कूलों की फीस आमतौर पर JNV और KV की तुलना में कहीं अधिक होती है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि निजी स्कूलों के कमजोर प्रदर्शन का असर भोपाल रीजन की रैकिंग पर भी पड़ा है। इसी कारण मध्य प्रदेश का भोपाल रीजन देश के 22 सीबीएसई रीजन में 19वें स्थान पर पहुँच गया। वहीं हर श्रेणी में छात्राओं ने छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया और भोपाल रीजन में लड़कियों करीब पांच प्रतिशत अंकों से आगे रहीं। सीबीएसई के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर प्रदर्शन जवाहर नवोदय विद्यालयों का रहा। JNV का कुल पास प्रतिशत 98.16% दर्ज किया गया। लड़कों का परिणाम 97.81% और लड़कियों का 98.73% रहा। विशेषज्ञों के अनुसार, नवोदय विद्यालयों की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था, अनुशासित माहौल और नियमित अकादमिक मॉनिटरिंग इसकी बड़ी वजह है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला यह मॉडल लगातार सफल साबित हो रहा

है। केंद्रीय विद्यालयों का प्रदर्शन भी मजबूत रहा। इनका कुल पास प्रतिशत 97.90% दर्ज किया गया। लड़कों का परिणाम 97.66% और लड़कियों का 98.11% रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रशिक्षित शिक्षक, राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम और नियमित मूल्यांकन केंद्रीय विद्यालयों की सफलता का आधार हैं। यही वजह है कि इनके परिणाम लगातार राष्ट्रीय औसत से बेहतर बने रहते हैं। एकलव्य मॉडल रजिस्ट्रेशन स्कूल (EMRS) का कुल पास प्रतिशत 85.47% रहा। लड़कों का परिणाम 83.46% और लड़कियों का 86.89% दर्ज किया गया। सीमित संसाधनों और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद यह प्रदर्शन सकारात्मक माना जा रहा है। यहाँ भी छात्राओं ने छात्रों से बेहतर परिणाम देकर बढ़ती शैक्षणिक जागरूकता का संकेत दिया। सरकारी स्कूलों का कुल पास प्रतिशत 80.60% रहा। लड़कों का रिजल्ट 79.86% और लड़कियों का 80.88% दर्ज किया गया। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि शिक्षकों की कमी और बुनियादी संसाधनों की चुनौतियों के बावजूद यह प्रदर्शन संतोषजनक है। हालाँकि, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल संसाधनों में सुधार से परिणाम बेहतर हो सकते हैं। सबसे चिंताजनक तस्वीर निजी स्कूलों की रही। सीबीएसई से संबद्ध इंटरनेट स्कूलों में सबसे अधिक 61,419 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 61,242 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। इसके बावजूद इन स्कूलों का कुल पास प्रतिशत केवल 76.85% रहा, जो सभी श्रेणियों में सबसे कम है। लड़कों का परिणाम 74.12% और लड़कियों का 80.02% दर्ज किया गया।

## बीएचईएल लेडीज लेडीज क्लब द्वारा संचालित कस्तूरबा अस्पताल स्थित वाटिका जलपान गृह के नवीनीकृत एक्सटेंशन काउंटर का लोकार्पण

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

बीएचईएल लेडीज लेडीज क्लब द्वारा संचालित कस्तूरबा अस्पताल स्थित वाटिका जलपान गृह के नवीनीकृत एक्सटेंशन काउंटर (PHARMACY) का लोकार्पण मुख्य अतिथि श्रीमती संगीता रामनाथन एवं श्रीमती रोजी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष बीएचईएल लेडीज क्लब की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ जिसका उद्देश्य मरीजों को खान-पान की शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर डॉ. (श्रीमती) पौमिला सचदेवा, महाप्रबंधक एवं मुख्य चिकित्सा सेवाएं, अन्य चिकित्सक एवं अधिकारियों, वाटिका सेंटर की उपाध्यक्ष श्रीमती प्रीति अग्रवाल, सचिव श्रीमती बीना बननवाल, कोषाध्यक्ष श्रीमती मंजू शौरी, श्रीमती शीतल जुनेजा सहित अन्य उपाध्यक्ष श्रीमती योगिता बघेल, श्रीमती अनुजा मजूमदार, श्रीमती ललिता चटर्जी, सहित श्रीमती मनीषा शर्मा, श्रीमती निशा मीना, श्रीमती दीपाली गोस्वामी एवं मैनेजर श्री सुमेर सिंह लोवंशी भी उपस्थित थे।



## मध्य प्रदेश निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रांत अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मितव्ययिता वरतने के निर्देश देने की मांग की

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

मध्य प्रदेश निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रांत अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव नीलू ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से यह मांग की है कि वर्तमान में प्रदेश निगम मंडलों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष अन्य पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों की गई है। उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी को खास तौर से वाहनों के उपयोग में मितव्ययिता बरतने की निर्देश/आदेश अविलम्ब जारी होना चाहिए। ताकि देश के प्रधानमंत्री जहाँ एक ओर सभी से पेट्रोल डीजल कम से कम खर्च करने की

बात कर रहे हैं, कम से कम गाड़ियों का उपयोग करने की बात कर रहे हैं। पलू सिस्टम लागू करने की बात कर रहे हैं। वहीं उनकी भावनाओं के विरुद्ध सैकड़ों गाड़ियों के साथ जुलूस ले जाकर वाहनों का दुरुपयोग करना वास्तव में प्रधानमंत्री की भावना के विरुद्ध है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जो निगम मंडल हानि में चल रहे हैं वहाँ पर नए अध्यक्षों या उपाध्यक्ष आदि अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होना चाहिए। संबंधित मंत्री या विभागीय ए सी एस या पी एस को अध्यक्ष बनाया जाए। पुराने आदेशानुसार सभी निगम मंडलों में एम

ओ यू(लक्ष्य पूर्ति करारनामा प्रथा फिर से लागू होना चाहिए, ताकि साल भर की गतिविधियों का लेखा जोखा बुरा एक बार समीक्षा बैठक में आए। उससे पता लगे कि राजनीतिक नियुक्तियों कारण सिद्ध हुई या सफेद हाथी साबित हुई। महासंघ के पदाधिकारी संयोजक अनिल बाजपेई, कार्यकारी अध्यक्ष अरुण वर्मा हेमंत कपूर, महामंत्री गजेंद्र सिंह कोठारी, बलवंत सिंह रघुवंशी, श्याम सुंदर शर्मा, आदि ने मुख्यमंत्री से इस मांग पहल कर प्रदेश स्तर पर कड़े आदेश प्रसारित करने का की मांग की है। ताकि देश हित में प्रदेश के राजनीतिक लोग इसका पालन कर सकें।

## गर्मी से राहत के लिए जैन सोशल ग्रुप मेन द्वारा श्रमिकों को राहत सामग्री वितरित



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

शोषण गर्मी को देखते हुए जेएसजी मेन 72 भोपाल\* के सदस्यों द्वारा पूर्व आईडी अमर जैन\* और अध्यक्ष पदम् सराफ के मार्ग दर्शन में राहत सामग्री का वितरण किया

गया। इस दौरान श्री दिगंबर जैन मंदिर स्मार्ट सिटी के पास निर्मित बिल्डिंग में कार्यरत श्रमिकों को अन्न सामग्री धूप से बचाव हेतु टोपी एवं गमछे का वितरण किया गया इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष चक्रेश जैन, अध्यक्ष पदम् सराफ, उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता बजाज, सचिव अमित

जैन, कार्यकारी सदस्य सुरेंद्र जैन, सरुन बजाज, शैलेंद्र लहरी, श्रीमती मधु जैन, श्रीमती राखी जैन, श्रीमती सीमा जैन एवं अन्य सदस्य मौजूद थे प्रवक्ता अंशुल जैन ने बताया जैन सोशल ग्रुप मेन निरंतर सक्रियता से सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहा है।

# आनंद विहार विद्यालय तुलसी नगर भोपाल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में छात्राओं ने बाजी मारी



SHREYA GUPTA - 91%    TANIYA ANAND - 90.4%    ADITYA PANT - 91.8%    ANUSHKA SAHU - 91.6%    DEEPSHIKHA YADAV - 91.2%    KASHISH TIWARI - 91.8%    LAVI JAIN - 92.4%    SUHANI SHARMA - 94.8%

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

आनंद विहार विद्यालय तुलसी नगर भोपाल में कक्षा बारहवीं का परीक्षा परिणाम अत्यंत उत्कृष्ट रहा। वाणिज्य संकाय में सुहानी शर्मा ने 94.8% के साथ

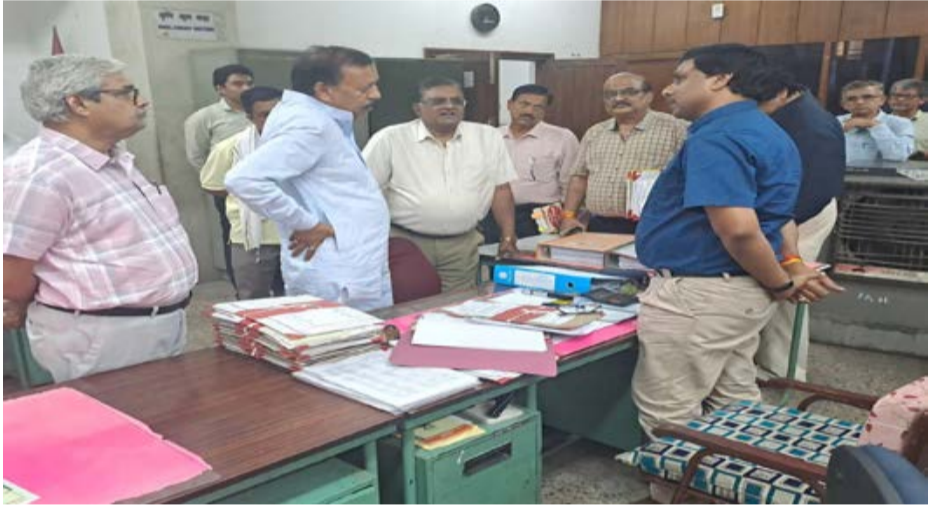
विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। लवी जैन 92.4%, कशिशा तिवारी 91.8%, आदित्य पंत 91.8%, अनुष्का साहू 91.6%, दीपशिखा यादव 91.8% अंक अर्जित कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। विज्ञान संकाय में श्रेया गुप्ता 91%

के साथ विद्यालय स्तर पर प्रथम एवं तानिया आनंद ने 90.4% द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कुल 100 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थियों ने अपने मुख्य विषयों में एक से अधिक विषयों में 90 से अधिक अंक अर्जित किया। सत्यम तिवारी और दीपशिखा यादव ने योगा ( ऐच्छिक विषय

) में 100 अंक अर्जित किया। वनिता समाज प्रेसिडेंट श्रीमती मधु सरन मैडम, विद्यालय चेयरपर्सन मैडम हिना बोस, मार्गदर्शक मैडम अर्चना बागची, सचिव मैडम कृष्णा विजयवर्गीय, कोषाध्यक्ष मैडम जीवन राव एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के समस्त सदस्यों ने इस उत्कृष्ट

परीक्षा परिणाम पर विद्यार्थियों को बधाई प्रेषित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय प्राचार्य श्री शैलेश झांषे एवं सभी शिक्षकों ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों को बधाई प्रेषित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

## अपेक्स बैंक के प्रशासक द्वारा शीर्ष बैंक मुख्यालय के विभिन्न कक्षों में भ्रमण किया गया



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री महेन्द्र सिंह यादव द्वारा बुधवार को शीर्ष बैंक मुख्यालय के विभिन्न कक्षों में भ्रमण कर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर कक्षा की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। उक्त अवसर पर श्री यादव के साथ बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता एवं वि.क.अ. अरुण मिश्रा भी साथ थे। भ्रमण के दौरान श्री यादव ने मुख्यालय के भूतल भवन स्थित सहायकी शाखा में क्लियरिंग सेक्शन एवं लॉकर रूम का भी भ्रमण किया।

## पहला जत्था चार धाम की यात्रा कर भोपाल पहुंचा एवं तीसरा जत्था मातृशक्ति का हरिद्वार से चार धाम के लिए रवाना



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

पहला जत्था चार धाम यात्रा की यात्रा कर भोपाल पहुंचा एवं तीसरा जत्था मातृशक्ति का हरिद्वार से चार धाम के लिए रवाना हुआ। ओम शिव शक्ति सेवा मंडल भोपाल के सचिव रिकू भट्टेजा बताया कि कि 30 अप्रैल को प्रकाश पाटिल के नेतृत्व में गया जत्था भोपाल वापस आ गया एवं महिला मंडल की अध्यक्ष दिव्या बोहरा के नेतृत्व में 37 महिलाओं का तीसरा जत्था भोपाल से 11 मई को रवाना हुआ था। 12 मई को हरिद्वार में गंगा आरती करने के उपरांत 13 तारीख को हरिद्वार से चार धाम यात्रा के लिए रवाना हुआ।



## वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी वर्ष 2026 के अंतर्गत जन जागरण के 13 अभियानों में एक महत्वपूर्ण नारी जागरण

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा अखंड दीपक एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी वर्ष 2026 के अंतर्गत जन जागरण के 13 अभियानों में एक महत्वपूर्ण नारी जागरण के तहत बुधवार को स्टेलिंग केशल कैम्पस के गणेश मंदिर में नारी जागरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थिति श्रीमती लेखा चौहान ने कहा कि आज भारतीय नारियाँ शिक्षित और भौतिक प्रगति की दौड़ में अग्रणी तो हैं लेकिन अपनी नारीत्व की गरिमा को भूल गई हैं। उन्होंने माता बहिनों से संस्कृति और समाज के उत्थान के लिए अपने समय साधना लगाने का आह्वान किया। जिला समन्वय समिति के सह समन्वयक श्री सुरेश श्रीवास्तव ने गायत्री परिवार संगठन के विराट होते स्वरूप और समाज और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका के बारे में बताया तथा संगठन से जुड़कर ईश्वरी कार्य में सहभागिता का बहिनों का आह्वान किया। कार्यक्रम में डॉ सुनील गुप्ता, श्रीमती रेखा तिवारी, श्रीमती हेमलता पटेल, श्री आर. बी. चौरीया आदि उपस्थित रहे।



## लघुकथा में अनावश्यक विस्तार और जानकारियां देने से बचें - डॉ. मिथलेश अवस्थी



दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

‘लघुकथा में अनावश्यक विस्तार और जानकारी देने से लघुकथा लेखकों को बचना चाहिए, लघुकथा का सम्यक मूल्यांकन करते समय विषय भाषा शिल्प और शैली पर पैनी दृष्टि रखना बहुत आवश्यक है।’ यह उद्गार हैं वरिष्ठ लघुकथा लेखक प्रो. मिथलेश अवस्थी नागपुर के जो लघुकथा शोध केंद्र समिति भोपाल द्वारा आयोजित बुधवारीय साप्ताहिक ऑन-लाइन गूगल गोष्ठी में सुपरिचित रचनाकार चित्रा राघव राणा यू. एस. ए. के लघुकथा पाठ पश्चात् विमर्श में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। इस आयोजन में चित्रा राघव राणा ने ‘बोझ’ बहिन -भाई के आत्मीय रिश्तों पर केंद्रित ‘अवर्द्ध’ बेटियों के साथ दौम्य व्यवहार को लेकर बुनी गई ‘कतरा -कतरा’ देश में पैदा हो रही विघटन की परिस्थितियों पर ‘अपनत्व’ अपने देश से विदेश में रहकर भी प्यार करने वालों के भाव तथा

‘लिपस्टिक और सिगरेट’ समाज में महिलाओं से लैंगिक भेदभाव की स्थिति पर लिखी गई लघुकथाओं का प्रभावी पाठ किया। इन लघुकथाओं पर वरिष्ठ साहित्यकार राजश्री शर्मा खंडवा ने मुख्य समीक्षक के रूप में अपनी बात रखते हुए इन लघुकथाओं को गहरी संवेदनाओं से संप्रकृत सामाजिक भावनाओं से भरी लघुकथाएं बताया। आयोजन के आरम्भ में शोध केंद्र की निदेशक काता रॉय ने स्वागत उद्बोधन दिया, कार्यक्रम का सफल सुमधुर संचालन डॉ.ममता माली मुंबई ने किया, इस आयोजन में डॉ. दिलीप बच्चानी, गोविन्द शर्मा, अनीता रश्मि, डॉ. गिरिजेश सक्सेना, चनश्याम मैथिल अग्रत ने भी अपनी महत्वपूर्ण पाठकीय टिप्पणियां प्रस्तुत की कार्यक्रम के अंत में रचनाकार चित्रा राघव ने सभी का आभार प्रकट किया आयोजन में देश विदेश के अनेक लघुकथा प्रेमी लेखक पाठक उपस्थित थे।

पानी सिर तक पहुंचा!



सवा दो महीनों तक आर्थिक मजबूती का गैर-जरूरी दिखावा करने के बाद आखिरकार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों" का मुकाबला करने के लिए सात-सूत्री अपील भारतवासियों से की है। तो आखिर ये नौबत आ पहुंची। प्रधानमंत्री को डॉलर और तेल- गैस बचाने के लिए आम नागरिकों से अपील करनी पड़ी है। सवा दो महीनों तक आर्थिक मजबूती का गैर-जरूरी दिखावा करने ( मुमकिन है जारी चुनाव के कारण किया गया हो ) के बाद अब नरेंद्र मोदी ने "चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों" का मुकाबला करने के लिए सात-सूत्री अपील भारतवासियों से की है। कहा है कि ऊर्जा बचाने के लिए उन्हें वर्क फ्रॉम होम को तरजीह देनी चाहिए, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर पेट्रोल- डीजल की खपत घटानी चाहिए, और रसोई ईंधन के इस्तेमाल में कटौती करनी चाहिए। विदेशी मुद्रा खर्च ना हो, इसके लिए साल भर उन्हें सोना नहीं खरीदना चाहिए, स्वदेशी उत्पादों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और विदेश यात्रा से बचना चाहिए। साथ ही रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल घटाने के लिए कुदरती खेती की ओर जाना चाहिए। ये बातें ऊर्जा, डॉलर, और उर्वरकों की संभावित किल्लत की ओर इशारा करती हैं। ईरान युद्ध ने विश्व ऊर्जा बाजार के स्वरूप को फिलहाल बदल दिया है। इसकी मार उन तमाम देशों पर पड़ी है, जिनके पास अपना ऊर्जा स्रोत नहीं है और अच्छे दौर में रणनीतिक भंडार बना लेने की बात जिनके दिमाग में नहीं आई। फिलहाल, बाजार में कच्चा तेल उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए (फरवरी की तुलना में) सवा से डेढ़ गुनी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव तेजी से बढ़ा है। इसी बीच विदेशी निवेशकों की भारत से पैसा निकालने के तेज होती गई रफ्तार और रुपये की कीमत में आई भारी गिरावट ने संकट और बढ़ा दिया है। उधर पश्चिम एशिया से घट आयात के कारण उर्वरक में इस्तेमाल होने वाले कैमिकल्स का अभाव हो गया है, जिससे खाद्य संकट की आशंकाएं गहराई हैं। ऐसे में कई देश पहले ही ऊर्जा एवं डॉलर बचाने के उपाय अपना चुके हैं। मगर भारत में बात तब शुरू हुई है, जब पानी सिर तक पहुंच गया है। तब भी बात सिर्फ नागरिकों तक है। जो भारतीय कंपनियां अरबों डॉलर का अमेरिका में कर रही हैं, उनमें देशभक्ति की भावना जगाने का आह्वान अभी नहीं किया गया है।

पैसा बांटो- राज करो!



सिर्फ विजय या स्टालिन को ही दोष क्यों दिया जाए? किसी राज्य या यहां तक कि केंद्र के बजट पर गौर करें, तो यही कहानी घटित होती दिखती है। पैसा बांटो, वोट खरीदो- सबका मकसद है। तमिलनाडु की सत्ता संभालते ही सी. जोसेफ विजय ने वो रोना रो दिया, जो अब राज्यों में बनने वाली हर नई सरकार के मुखिया करते हैं! आरोप लगाया कि पूर्व डीएमके सरकार राजकोष को बदहाल छोड़ गई है, जिसका ब्योरा उनकी सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर देगी। कहा कि राज्य पर दस लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इसके बावजूद थलापति ( कर्मांडर ) पुकारे जाने वाले नए मुख्यमंत्री ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का एलान कर दिया। इससे हर साल 1,700 करोड़ रुपये से ज्यादा का नया बोझ राजकोष पर पड़ेगा। वैसे, यह सिर्फ झंकी है। वादों की अपनी लंबी लिस्ट को उन्होंने निभाया, तो उस पर सालाना एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च आएगा। 3.31 लाख करोड़ रुपये के बजट वाले इस राज्य में फिलहाल 65 हजार करोड़ रुपये की वो "कल्याण योजनाएं" भी हैं, जिन्हें डीएमके सरकार ने शुरू किया था। जिस राज्य में राजस्व का 62 फीसदी हिस्सा तनखाह, पेंशन, और ब्याज चुकाने पर खर्च होता हो, वहां ऐसा "जिन कल्याण" सिर्फ नया ऋण लेकर ही किया जा सकता है! हर कर्ज नया नहीं होता, बसोंतें उसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था एवं समाज की बुनियाद मजबूत करने के लिए किया जाए। इससे भविष्य में राजस्व बढ़ता है, जिससे विकसित समाज बनाने का मार्ग प्रशस्त होता है। जबकि ऋण लेकर उधोगों में खर्च करना असल में भविष्य को दांव पर लगाना होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्टालिन हों या विजय, अथवा अन्य राजनीतिक दल एवं नेता- इस अनुभव सिद्ध तथ्य को नजरअंदाज किए रहते हैं। याद करने योग्य है कि 2021 में मुख्यमंत्री बनने पर डीएमके नेता एम.के. स्टालिन ने पूर्व एडीएमके सरकार पर खाली खजाना छोड़ जाने का आरोप लगाया था। मगर, नकदी ट्रांसफर की अपनी योजनाएं चलाने से वे बाज नहीं आए। वैसे सिर्फ उन्हें या विजय को ही दोष क्यों दिया जाए? किसी राज्य या यहां तक कि केंद्र के बजट पर गौर करें, तो यही कहानी घटित होती दिखती है। बुनियाद मजबूत करना आज किसी की प्राथमिकता नहीं है। पैसा बांटो, वोट खरीदो- सबका मकसद है। हर श्वेत पत्र इसी अंधकारमय सच्चाई को उजागर करता है।

जनता संयम करें, सत्ता उड़ान भरे!

तो अब जनता के लिए संयम का समय है। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुपचाप परदा हटा दिया। असलियत सामने आई। देशवासियों से कहा गया—विदेश यात्राएं टालिए, ईंधन-तेल कम खर्च कीजिए, गाड़ियों साइज़ कीजिए, घर से काम कीजिए। हमेशा की तरह भाषा सधी हुई थी। आवाज में चिंता थी, ठहराव था, और तकलीफों पर हल्का-सा राष्ट्रवाद चढ़ा हुआ था। संदेश साफ था, संकट आया है तो जनता अपनी कमर कसे, देशभक्ति दिखाएं, त्याग को तैयार रहे! हैदराबाद के भाषण ने केवल यह नहीं बताया कि भारत संकट के दौर में है। भाषण ने वास्तव में कुछ और उजागर किया। यह कि भारत में व्यवस्था पर दबाव बढ़ने पर बोझ उठाने की अपेक्षा आखिर किससे की जाती है? केवल आम लोगों से। देश से धीरे-धीरे कहा जा रहा है कि कम खर्च करो, कम यात्रा करो, कम उम्मीद रखो, और इस समायोजन को देशभक्ति समझो। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का जुमला बोला और कहा कि भारत का भविष्य "रोजमर्रा के जीवन में लिए गए सचेत निर्णयों" से तय होगा। निश्चित रूप से कॉरपोरेट भारत से नहीं, जिसकी विदेशी कॉन्फ्रेंस, एग्जीक्यूटिव रिट्रीट और विदेश यात्राएं संयम की अपील से अप्रभावित हैं। उस अरबपति वर्ग से नहीं, जिसकी संपत्ति पिछले दशक के लगभग हर संकट के साथ बढ़ी है, जबकि शीर्ष एक प्रतिशत आबादी अब देश की 40 प्रतिशत से अधिक संपत्ति पर नियंत्रण रखती है। उन मंत्रियों से भी नहीं, जिनके विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करते हैं और फिर चुपचाप सार्वजनिक चर्चा से गायब हो जाते हैं।

निश्चित ही स्वयं प्रधानमंत्री से भी नहीं। नागरिकों से विदेश यात्राओं पर पुनर्विचार करने की अपील के बाद नरेंद्र मोदी यूरोप और खाड़ी देशों की बहुदेशीय यात्रा पर निकल पड़े—नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली और यूएई। व्यापार, ऊर्जा और सहयोग पर वे बातचीतें, जो सरकार की अपनी डिजिटल दक्षता और वर्क फ्रॉम होम वाली भाषा के अनुसार, उन्हीं वीडियो कॉन्फ्रेंसों पर भी हो सकती थीं जिनकी सलाह देश को दी गई थी। विदेशी धरोहराभास संयोग नहीं है। यह व्यवस्था की बनावट में मौजूद है। प्रस्तावित त्याग कभी सचमुच राष्ट्रीय नहीं होता। वह नीचे की ओर निर्देशित रहता है—मध्यवर्ग, निम्न मध्यवर्ग, किसान, वेतनभोगी परिवार और छोटे व्यापारी की ओर। उस भारत की ओर, जो व्यवस्था में दारु पड़ते ही सबसे पहले खर्चें बांधता है। उन भारतीयों की ओर, जिनके लिए सोना विलासिता नहीं, सुरक्षा है। किसी नीति-निर्माता को सोना केवल आभूषण या राष्ट्रीय हित में टाली जा सकने वाली वस्तु लग सकती है। लेकिन भारत में लोग सोने को आर्थिक रिपोर्ट की तरह नहीं देखते। फसल से पहले वही गिरवी रखते हैं। जिन परिवारों में बेटियों के हिस्से कुछ और नहीं आता, वहां वही उनका उत्तराधिकार होता है। स्थिर वित्तीय ढांचे से बाहर करोड़ों लोगों के लिए वही उस सामाजिक सुरक्षा का सबसे निकट विकल्प है, जिसे भारत गणराज्य कभी बना नहीं सका। परिवारों से सोना खरीद डालने को कहना केवल आर्थिक अपील नहीं है। यह उनसे उस सुरक्षा जाल को स्थगित करने को कहना है, जिसे उपलब्ध कराने में राज्य विफल रहा है। शायद यही आधुनिक भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी कुशलता या बेईमानी है। अपनी आर्थिक गड़बड़ियों और असुरक्षा को जनता की नैतिक जिम्मेदारी करार दो। संस्थागत सहारा जितना कमजोर होता है, त्याग की भाषा उतनी ऊंची हो जाती है। नागरिकों से अब केवल अस्थिरता झेलने की अपेक्षा नहीं की जाती। उनसे उसे नैतिक गरिमा के साथ झेलने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए इसके बाद जो दृश्य सामने आया, वह संयोग कम और खुलासा अधिक लगा।

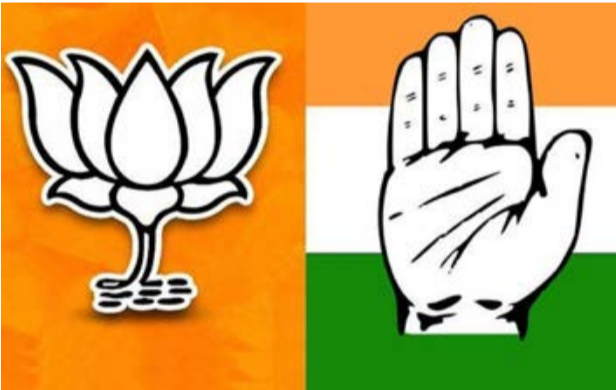


नागरिकों से संयम, त्याग और कम उपभोग की अपील के चौबीस घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि गुजरात प्रदर्शन की तैयारी में जुटा हुआ आ। प्रधामंत्री मोदी का भव्य रोड शो सोमनाथ से गुजरा। काफिले, भीड़, भगवा झंडे, डेढ़ किलोमीटर तक खड़े कलाकार और मंदिर नगरी से गुजराता योजनाबद्ध विजय प्रदर्शन। सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के 75 वर्ष पूरे होने पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एशबैटिक टीम के छह हॉक एमके-132 विमानों ने अरब सागर के ऊपर केसरिया, सफेद और हरे रंग की लकीरें खींचीं। फिर बड़ोदरा में दूसरा रोड शो, दूसरा उद्घाटन, शांक्ति का एक और सार्वजनिक प्रदर्शन। दो दिन में तीन शहर। छह लड़ाकू विमान। दो रोड शो। लेकिन वहां किसी ने संयम की बात नहीं की। मीडिया में कोई यह हिसाब नहीं लगा रहा था कि काफिलों, विमानों और पूरे तमाशों में कितना ईंधन खर्च हुआ। हैदराबाद भाषण में सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली बात वह नहीं थी जो कही गई। बल्कि वह थी, जिसे कहना अब जरूरी नहीं समझा गया। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव क्यों है, इसका कोई स्पष्ट हिसाब नहीं दिया गया। वर्षों से टाले गए संरचनात्मक सुधारों पर कोई आत्ममंथन नहीं हुआ। आत्मनिर्भरता के दावों के बावजूद भारत वैश्विक झटकों के प्रति कितना संवेदनशील बना हुआ है, इसका कोई ईमानदार स्वीकार नहीं था। आखिर सरकार का बिल आपके खाने की मेज पर नहीं पहुंचता। आपका पहुंचता है। यही वह नई कारीगरी है जिसने भारत में पुराने सामाजिक अनुबंध की जगह ले ली है। गणराज्य का पुराना वादा कठिन था, लेकिन स्पष्ट था—आप राज्य को अपना वोट, टैक्स और भरोसा देते हैं तो बदले में सरकार से अपेक्षा होती है कि संकट घर तक पहुंचने से पहले उसे सरकार अपने भीतर सोख ले।

आज का नया इंतजाम अलग है। आप सरकार को अपना वोट दें, उसे जिताने, टैक्स और विश्वास भी दें, लेकिन जब अर्थव्यवस्था कमजोर पड़े या संकट आए, तब अपनी ही कमर कस लीजिए। खर्च घटाइए। अपनी सुरक्षा तक टाल दीजिए। महीने का बजट थोड़ा और खींचिए, जबकि प्रधानमंत्री, मंत्री और सरकार चमचमाते मंचों से अपने तमाशो करते रहें। इसलिए एक तरफ वह कॉरपोरेट वर्ग है, जिसकी विदेश यात्रा का बजट मध्यवर्ग के सिकुड़ने के साथ भी बढ़ता रहता है। आखिर वे अरबपति हैं, जिनकी संपत्ति हर संकट के साथ और बढ़ती गई। फिर वह राजनीतिक प्रतिष्ठान है, जिसके रोड शो, एयर शो और विदेशी दौरों की भूख जनता के पैसे पर बेखटके चलती है। उस पर मितव्ययिता की कोई सीमा लागू नहीं होती। दूसरी ओर वह बेरोजगार स्नातक है जिसे नौकरी नहीं मिल रही, वह परिवार है जो कर्ज को अगले महीने तक घसीट रहा है, वह किसान है जो ऋण के लिए चांदी-सोना गिरवी रखता है, और वह घर है जिससे प्रधानमंत्री अब राष्ट्रीय हित में बेटी के गहने खरीदने को टाल देने के लिए कह रहे हैं। उस नाते प्रधानमंत्री के 10 मई के भाषण ने आखिरकार यही उजागर किया। यह लीडरशिप का क्षण नहीं था, बल्कि अनायास आई पारदर्शिता से लोगों को संकट के लिए तैयार करने का क्षण था। क्योंकि जब कोई सरकार संकट में सबसे पहले नागरिकों के सोने की ओर देखती है, तब वह कॉरपोरेट से अपील नहीं कर रही होती। वह अपनी संयम और अपनी कटौती नहीं बता रही होती। वह लोगों को छुड़ी रह करने को कह रही होती है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद तुरंत यूरोप की उड़ान भरते हैं। सो लब्बोलुआब क्या? भारत में त्याग के लिए भी एक वर्ग तय है—मध्यवर्ग, यानी आम जन। -श्रुति व्यास

परजीवी होने में भाजपा और कांग्रेस का अंतर!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी कहा है। उन्होंने कई बार पहले भी यह बात कही है। इस बार रविवार को दक्षिण भारत के दौरे पर उन्होंने यह बात कही। यह संयोग है कि जिस समय प्रधानमंत्री ने यह तंज किया उस समय तमिलनाडु की नई सरकार शपथ ले रही थी और मंच पर मुख्यमंत्री विजय के साथ राहुल गांधी भी बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब परजीवी पार्टी हो गई है। यह बात एक स्तर पर सही है। हालांकि अभी जिन तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वह सरकार उसने अपने दम पर बनाई है। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में उसे अकेले पूर्ण बहुमत है। उसने किसी सहयोगी पार्टी के साथ भी चुनाव नहीं लड़ा था। चौथा राज्य केरल है, जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहां जरूर वह एक गठबंधन के साथ लड़ी थी। फिर भी कांग्रेस ने 140 के सदन में 63 सीटें अकेले जीती है। यानी वह बहुमत के करीब अपने दम पर पहुंच गई है। अगर कांग्रेस को दूसरी पार्टियों पर निर्भरत की बात करें तो कुछ राज्य पार्टियां हैं, जहां कांग्रेस निर्भर है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश आदि।



लेकिन ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस हारे या जीते अकेले ही राजनीति करती है। एक श्रेणी ऐसे राज्यों की है, जहां कांग्रेस गठबंधन में है लेकिन उसकी ताकत भी कम नहीं है और वहां गठबंधन नहीं होने से प्रादेशिक पार्टियों को नुकसान हो सकता है। बहरहाल, एक समय ऐसा भी रहा है, जब थोड़े राज्यों को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह गठबंधन के सहारे ही चलती रही है। देश के

डीएमके या डीएमके से उसका तालमेल रहता था तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ। पंजाब में वह अकाली दल के दम पर खड़ी थी तो हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के दम पर। अब अगर कांग्रेस और भाजपा के फर्क की बात करेंगे तो वह भी साफ दिखाई देगा। कांग्रेस जिन पार्टियों के साथ भी चुनाव से ज्यादातर पार्टियां आज भी हैं और मजबूत हैं। दूसरी ओर भाजपा जिन पार्टियों के

साथ रही वे आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। जीव विज्ञान में परजीवी यानी पैरासाइट उन सूक्ष्म जीवों को कहते हैं जो दूसरे का रक्त चूस कर जीवित रहते हैं। कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं, जो होस्ट को भी जीवित रखते हैं और खुद भी जीवित रहते हैं। लेकिन कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं, जो होस्ट का समाप्त कर देते हैं। अलग अलग राज्यों में भाजपा के जो सहयोगी थे उनकी स्थिति देखें तो एक साफ तस्वीर सामने आती है। महाराष्ट्र में शिव सेना बड़ी ताकत थी। उसके दम पर भाजपा आगे बढ़ी लेकिन आज शिव सेना और ठाकरे परिवार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। बिहार में जनता दल यू बड़ी पार्टी थी। आज उसकी जगह भाजपा सरकार में है और जदयू के सामने अस्तित्व का संकट है। पंजाब में अकाली दल और हरियाणा में इनेलो लगभग समाप्त हो गए हैं। ओडिशा में बीजू जनता दल की स्थिति भी ऐसी ही है। झारखंड में आजसू के सामने भी अस्तित्व का संकट है। अभी भाजपा के साथ जो भी सहयोगी हैं वे सब भाजपा की कृपा पर हैं। अब किसी का ऐसा अस्तित्व नहीं है कि वह स्वतंत्र राजनीति कर सके।

तेल के संकट की याद तो आई!

आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेल के संकट की याद आ गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको इसके बारे में पता नहीं था। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस का संकट तो करीब ढाई महीने पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन चूँकि उस समय चुनाव चल रहे थे। इसलिए उस समय लोगों को बताया गया था। अब संकट के बारे में बताने का सही समय आ गया है। प्रधानमंत्री पहले भी जानते थे कि देश में तेल के कुएं नहीं हैं। लेकिन यह बात उन्होंने देश के लोगों को तब बताई जब पांच राज्यों के चुनाव समाप्त हो गए। रविवार, 10 मई को जब वे कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर थे तब उन्होंने हैदराबाद की अपनी सभा में कहा कि भारत के लोग किफायत से पेट्रोल, डीजल और गैस का इस्तेमाल करें क्योंकि भारत के पास तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत के पास जो भंडार है उसमें भी कमी आ गई है। तभी यह बताने की जरूरत महसूस हुई है। अगर पांच राज्यों में चुनाव नहीं चल रहे होते तो प्रधानमंत्री यह बात पहले ही बताते। लोगों को आगाह करते कि पड़ोस के देश में युद्ध चल रहा है और भारत पर इसका बड़ा असर हो सकता है। इसलिए लोग तेल सोच समझ कर खर्च करें। लेकिन उस समय तो पेट्रोल, डीजल और गैस के संकट को लेकर प्रधानमंत्री या उनकी सरकार के किसी मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। उल्टे प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हवाई जहाज उड़ते रहे, जनसभाएं होती रहीं, रैलियां व रोड शो होते रहे। सवाल है कि क्या उनमें पेट्रोल, डीजल और गैस का खर्च नहीं हो रहा था? क्या थोड़ी रैलियां और रोड शो कम करके तेल नहीं बचाया जा सकता था? बमहाल, अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया। उसके दो हफ्ते बाद 16 मार्च को पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई। ईरान पर हमले के बाद एक मार्च से लेकर 10 मई तक एक बार भी सरकार की ओर से नहीं कहा गया कि तेल का संकट है। एक बार भी लोगों से अपील नहीं की गई कि वे संयम बरतें। हालांकि कई फैसले ऐसे हुए, जिससे लोग संयम बरतने को मजबूर हुए। जैसे कॉमर्शियल गैस की स्पलाई कम कर दी गई। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत सीधे तीन हजार रुपए से ज्यादा कर दी गई।



विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत बढ़ा दी गई। विमानन कंपनियों के अधिकतम किराए पर लगी रोक को हटा लिया गया। सो, अपने आप लोग मजबूर हुए संयम बरतने के लिए। लेकिन जैसे ही पांच राज्यों के चुनाव खत्म हुए और सरकारों का गठन शुरू हुआ वैसे ही तेल संकट की चेतावनी आ गई और लोगों को संयम बरतने की नसीहत दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया। वे सिर्फ इतना कह कर नहीं रुक गए कि भारत के पास तेल के कुएं नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। कारपूँिंग करनी चाहिए। जिस तरह कोरोना की महामारी के समय किया उस तरह से वर्क फ्रॉम होम अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने किसानों से रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कम करने और जैविक खाद की ओर यानी गोबर आदि की ओर लौटने को भी कहा। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को विदेश यात्राएं स्थगित करनी चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से सोने की खरीद कम करने की सलाह भी दी। सोचें, कितनी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोग विदेश घूमने नहीं जाएं और सोना

नहीं खरीदें! इसका अर्थ है कि तेल का संकट गहरा है। यह पहले भी था लेकिन पहले चूँकि चुनाव चल रहे थे और उसके बीच अगर लोगों को इस तरह की नसीहत दी जाती तो चुनाव में नैरेटिव बिगड़ सकता था। इसलिए उस समय लोगों से कहा गया कि कोई संकट नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ काबू में कर लिया है। यह धारणा बनवाई गई कि दुनिया के देशों में संकट है लेकिन भारत में चूँकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं इसलिए कोई संकट नहीं है। दूसरी ओर दुनिया के दूसरे सभ्य व लोकतांत्रिक देशों ने इस तरह के उपायों के बारे में अपने नागरिकों को युद्ध शुरू होते ही बता दिया था। कई देशों ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कराया और तेल की खपत कम करने के दूसरे उपाए आजमाने शुरू किए। विमानों की उड़ानों में कटौती की गई। लोगों के वेतन, भत्ते आदि घटाए गए। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाई गईं। लेकिन भारत में विधानसभा चुनावों के खत्म होने का इंतजार किया गया। उसके बाद इस संकट के बारे में बताया गया। अब प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसके खतरे को समझने की जरूरत है। असल में दुनिया के किसी दूसरे देश के मुकाबले भारत के लिए चिंता ज्यादा है। भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी तेल आयात करता है। अपनी जरूरत का 60 फीसदी से ज्यादा गैस भी भारत आयात करता है। लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। युद्ध रुका हुआ है फिर भी होमुंज की खाड़ी नहीं खुल रही है, जहां से भारत का 40 फीसदी तेल आता है। इसके अलावा खाड़ी के दूसरे देशों पर ईरान के हमले से तेल के कुओं को नुकसान हुआ तो तेल व गैस के संयंत्र भी नष्ट हुए हैं। इससे तेल के दाम बढ़े। सो, अगर सब कुछ सामान्य हो जाए तब भी तेल की आपूर्ति बहाल होने और कच्चे तेल की कीमत युद्ध से पहले की स्थिति तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। इसका अर्थ है कि भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति कम रहेगी और कीमत ज्यादा देने होगी। इससे भारत का आयात बिल बढ़ेगा जिसका असर भारत के विदेशी

मुद्रा भंडार पर पड़ेगा। भारत के साथ दूसरा संकट यह है कि देश में तेल व गैस के भंडारण की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। तभी घरेलू आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इसका तेल व गैस पर आधारित दूसरे उद्योगों पर बहुत बड़ा असर हुआ है। हजारों की संख्या में फैक्टरियां बंद हुईं या उत्पादन कम हुआ है। इससे रोजगार के अवसर घटे हैं और मजदूरों का पलायन हुआ है। दूसरी ओर दुनिया देशों का बाजार जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आण्टिकारों और नए उत्पादों के दम पर ऊपर जा रहा है उस क्षेत्र में भारत शून्य है। यही कारण है कि बाजार का वेटेज लगातार कम होता जा रहा है और ताड़वान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों का वजन बढ़ रहा है। ताड़वान की एक कंपनी की बाजार पूंजी शेयर बाजार में सूचीबद्ध भारत की सभी कंपनियों की सामूहिक पूंजी से ज्यादा हो गई है। सो, अर्थव्यवस्था को लेकर भारत के बारे में विश्व की धारणा व्यापक रूप से प्रभावित हुई है। इसे लेकर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर रूचिर शर्मा ने पिछले दिनों कहा था कि वे 30 साल से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के क्षेत्र में हैं और कभी भी भारत के प्रति ऐसी उदासीनता देखने को नहीं मिली। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के बारे में सोच ही नहीं रही है। यह एक अलग आर्थिक संकट का संकेत है। बहरहाल, प्रधानमंत्री ने पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर जिस तरह की सलाह और चेतावनी दी है वह संकट की गंभीरता बताने वाला है। इसका अर्थ है कि आने वाले कुछ समय तक भारत में ईंधन का संकट रहेगा। आगे कुछ दिनों में पेट्रोल, डीजल व गैस की कीमतों में इजाफा हो तब भी हैरानी नहीं होगी। अगर ईंधन महंगा होता है तो फिर जरूरत की सभी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। यानी महंगाई का नया दौर शुरू होगा। एक तरफ रोजगार कम हो रहे हैं तो दूसरी ओर कीमतें बढ़ेंगी। इसके बावजूद आपूर्ति सामान्य रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। वह गारंटी करने के लिए सरकार को अपनी खरीद में विविधता लाने के साथ साथ भंडारण की व्यवस्था को बेहतर करना होगा। इसके साथ ही ऊर्जा के दूसरे स्रोतों में बढ़ा निवेश करना होगा ताकि आयातित तेल पर निर्भरता कम हो।

-अजीत द्विवेदी



# भारत में बैलेस्टिक मिसाइलों का ताबड़तोड़ प्रोडक्शन, कुछ बड़ा होगा

एजेंसी नई दिल्ली

भारत ने अपनी मिसाइल ताकत को लगातार मजबूत किया है। फिर चाहे ड्रॉस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें हो या फिर अनिन सीरीज की बैलेस्टिक मिसाइलें। भारत आज दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुका है और सबसे बड़ी बात इन अत्याधुनिक मिसाइलों के पीछे डीआरडीओ की बड़ी भूमिका रही है। रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है क्योंकि भारत सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी इस सेक्टर में एंट्री देने की तैयारी में है। दरअसल दिल्ली में आयोजित कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने खुद यह बात कही कि निजी क्षेत्र के साथ और ज्यादा काम करने के अन्य पहलुओं पर चर्चा चल रही है। उनका मानना है कि मिसाइल उत्पादन को क्षेत्र है जहां अब तक एरोस्पेस के हिस्से के रूप में अधिकांश ऑर्डर लगभग पूरी तरह एक ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को दिए जाते रहे। यह बात हम सब जानते हैं कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में अगर भारत में किसी का दबदबा है तो वह डीआरडीओ है। डीआरडीओ ने आज कई घातक मिसाइलें बनाई हैं।

रक्षा सचिव ने जैसा कि जानकारी दी कि भारत सरकार निजी क्षेत्र की ओर भी देख रही है। यानी कि आगे चलकर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें प्राइवेट कंपनी का भी बड़ा रोल हो सकता है। रक्षा सचिव ने कहा कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि बदलते युद्ध के स्वरूप को देखते हुए फिलहाल निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। देखिए रक्षा सचिव ने क्या कुछ कहा। बट इन टर्म्स ऑफ दी अदर एलिमेंट्स ऑफ यू नो थिंग्स दैट वी कैन डू मोर विथ द प्राइवेट सेक्टर। युद्ध का तरीका बदल चुका है। आज मिसाइलें और ड्रोन फ्रंट लाइन में हैं। कहीं भी कोई देश लड़ रहा है तो सबसे ज्यादा हथियार जो इस्तेमाल में आ रहे हैं वो ड्रॉस हैं। मिसाइलें हैं। आज



जिस देश के पास घातक मिसाइलें हैं वो अपनी सीमा की सुरक्षा कर सकता है। ऐसे में भारत बड़े स्तर पर मिसाइल प्रोडक्शन करना चाहता है। और रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव तक दुनिया ने देखा कि आज मिसाइलें सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का साधन नहीं बल्कि युद्ध जीतने का निर्णायक हथियार बन चुकी हैं। ऐसे में भारत को भी अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को बड़े स्तर पर बढ़ाने की जरूरत है। रक्षा सचिव ने कहा कि अब तक मिसाइल निर्माण के अधिकार ऑर्डर सरकारी कंपनियों को दिए जाते रहे हैं। लेकिन सरकार अब इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी अवसर देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की बैलेस्टिक

मिसाइलों की टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करने की इच्छा बढ़ रही है और उनके अनुसार अब वो समय आ चुका है जब इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए सरकार का यह कदम इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि अभी भारत में कुछ ही कंपनियां हैं जो घातक मिसाइलें बना रही हैं। ज्यादातर ऑर्डर डीआरडीओ के पास हैं। तो ऐसे में डीआरडीओ के ऊपर भी एक बड़ा बोझ है। डीआरडीओ कई तरह की मिसाइलों पर काम कर रहा है। तो अगर ऐसे में प्राइवेट कंपनियों का साथ मिलता है या फिर प्राइवेट कंपनियां इस क्षेत्र में घुसती हैं तो एक तरह से एक बोझ भी कम होगा और बड़े स्तर पर बड़े स्केल पर मिसाइल का प्रोडक्शन होगा।

# अफगानिस्तान हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा, तालिबान पर भड़का पाकिस्तान, बोला- भारत जैसा हाल करेंगे

एजेंसी इस्लामाबाद

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को युद्ध की चेतावनी दी है। उन्होंने अफगान तालिबान को भारत का प्रॉक्सी बताया और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को पनाह देने का आरोप लगाया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर तालिबान नहीं मानता है तो पाकिस्तान उसी तरह जवाब देगा जैसा उसने पिछले साल भारत के खिलाफ दिया था। पाकिस्तान का दावा है कि उसने पिछले साल मई में हुए संघर्ष के दौरान भारत को जबरदस्त शिकस्त दी थी, हालांकि वह अपने दावे के समर्थन में आज तक एक भी सबूत पेश नहीं किया है। वहीं, भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेसों को बर्बाद किया था। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा: "अगर वे तैयार नहीं हैं, तो हमने दिल्ली के साथ जो किया, वही हम काबुल के साथ भी करेंगे।" उन्होंने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान अरसल में भारतीय नीति का एक जरिया बन गया है। आसिफ ने कहा, "इस समय, अफगानिस्तान भारत का प्रॉक्सी बन गया है।" उन्होंने आगे जोड़ा: "काबुल हमारे खिलाफ हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है।" पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि "इस समय दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं है।"

पिछले साल मरका-ए-हक में भारत की हार के बाद अल्लाह का शुकू है वे अब हमारे साथ सीधे टकराव में उतरने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। इसलिए, अब पूरी लड़ाई काबुल के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही है। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने तुर्की, सऊदी अरब और कतर जैसे कूटनीतिक चैनलों के



जरिए अफगानिस्तान से बातचीत करने की बार-बार कोशिश की, लेकिन उन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा, "कतर में बातचीत के दौरान, अफगानिस्तान हर बात पर सहमत हो गया था, लेकिन बाद में उसने गारंटी देने से मना कर दिया।" उन्होंने कहा कि काबुल जुबानी तौर पर सहमत होने को तैयार था, लेकिन लिखित में नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुख्य मांग काबुल से एक लिखित वादा था, जिसमें यह पक्का किया जाए कि अफगान जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने के लिए नहीं किया जाएगा और वहां काम कर रहे आतंकवादियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि अगर काबुल आतंकवाद के खिलाफ लिखित भरोसा देता है, तो पाकिस्तान बातचीत के लिए अब भी तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा के बत्रू में हाल ही में हुए एक हमले का जिक्र करते हुए आसिफ ने कहा कि कई लोग मारे गए हैं और पाकिस्तानी सेना लगातार कुर्बानियां दे रही है। उन्होंने कहा, "इस हालात की वजह से हमें युद्ध में धकेला जा रहा है," उन्होंने कहा कि अब नई दिल्ली अफगानिस्तान के जरिए काम कर रही है।

# ईरान का दूसरे देशों के साथ संबंध भारत के खिलाफ नहीं: पाकिस्तान से दोस्ती पर तेहरान की सफाई

एजेंसी तेहरान

ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दूसरे देशों के साथ ईरान के संबंध कभी भी भारत के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत द्विपक्षीय संबंधों का मकसद किसी तीसरे देश को निशाना बनाना नहीं होना चाहिए। ईरान का यह बयान तब आया है, जब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ब्रिक्स (BRICS) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत का दौरा करने वाले हैं। भारत में ईरान के पाकिस्तान की बढ़ते संबंधों को लेकर शंका जताई जा रही है। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। उसने ईरान के सैन्य विमानों को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए अपने देश में शरण भी दी थी।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा कि दूसरे देशों के साथ ईरान के संबंध कभी भी भारत के खिलाफ नहीं रहे हैं। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है कि कोई भी द्विपक्षीय संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बाकाई ने यह भी कहा कि सैन्य क्षेत्र में ईरान के पास



समझौते से अमेरिका के पीछे हटने और IRGC कुदस फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या जैसी घटनाओं का उदाहरण दिया। उन्होंने युद्ध को खत्म करने और होमूज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान के हालिया जवाबी प्रस्ताव के बारे में भी बताया, जिसे अमेरिका ने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा, "नाकेबंदी अपने आप में युद्ध की घोषणा मानी जाती है।" उन्होंने होमूज जलडमरूमध्य संकट और ऊर्जा संकट के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान और ईरान के संबंधों में हाल के दिनों में तेजी देखी गई है। इजरायल और अमेरिकी हमले के बाद दोनों देश एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच खुद को मध्यस्थ के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। हालांकि, वह मध्यस्थता की आड़ में अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत की चिंता बढ़ गई है। ऐसी आशंका है कि पाकिस्तान, ईरान के साथ संबंधों का इस्तेमाल भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है।

एक महत्वपूर्ण "सरप्राइज क्षमता" मौजूद है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर ईरान की प्रतिक्रिया पर भी बात की। ईरानी प्रवक्ता का यह बयान तब आया है, जब दोनों पक्षों के बीच 40 दिनों से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए संघर्ष-विराम पर सहमति बने हुए एक महीना बीत चुका था। बाकाई ने अमेरिका के साथ ईरान के कूटनीतिक तनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने 2015 के ईरान परमाणु

# काबुल में नया मिशन! भारत-अफगानिस्तान के बीच 46 मिलियन डॉलर की क्या बड़ी डील हुई

एजेंसी नई दिल्ली

भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई मजबूती देते हुए 46 मिलियन डॉलर से अधिक की बड़ी डील हुई है। भारतीय कंपनी TCRC ने अफगान नेशनल स्टेडडर्स अथॉरिटी (ANSA) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत काबुल और अफगानिस्तान के 9 प्रमुख सीमा चौकियों पर एडवांस्ड लेब बनाई जाएंगी। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में आयात-निर्यात से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता जांच और मानक प्रणाली को पहले से और मजबूत करना है। नई लेब्स के जरिए खाद्य पदार्थों, दवाओं, कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामानों की टेस्टिंग अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार की जा सकेगी। इससे सीमा पार व्यापार को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। काबुल समेत 9 बॉर्डर क्रॉसिंग पर हॉगी हार्डवेक लेब्स



समझौते के तहत काबुल के अलावा अफगानिस्तान की प्रमुख सीमा चौकियों पर आधुनिक उपकरणों से लेब्स स्थापित की जाएंगी। इन प्रयोगशालाओं में

गुणवत्ता परीक्षण, प्रमाणन और सुरक्षा मानकों की जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। माना जा रहा है कि इससे अफगानिस्तान की व्यापारिक क्षमता और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ा फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डील भारत और अफगानिस्तान के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने वाली है। राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत लगातार अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट्स में सहयोग करता रहा है। यह नई साझेदारी दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है, दोनों देशों के लिए यह फायदेमंद है।

# ट्रंप के बीजिंग पहुंचते ही अमेरिका पर क्यों भड़का चीन? बोला- संप्रभुता से समझौता बर्दाश्त नहीं



एजेंसी बीजिंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग पहुंचते ही चीन ने वाशिंगटन की जमकर आलोचना की है। चीन ने यह आलोचना ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री को लेकर की है। उसने अमेरिका से अपने वादों का सम्मान करने को कहा है। चीन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली दो दिवसीय बैठकों के दौरान ताइवान निश्चित रूप से चर्चा का विषय होगा। चीन लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है और बलपूर्वक उस पर अधिकार की धमकी भी देता है। इसके अलावा वह ताइवान के साथ किसी भी देश के संबंधों का कड़ा विरोध भी करता है। दिसंबर में, ट्रंप प्रशासन ने ताइवान के लिए 11 अरब डॉलर के हथियारों के पैकेज की घोषणा की थी, जो अब तक का सबसे बड़ा पैकेज था। इस पर चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय की प्रवक्ता झांग हान ने कहा कि ताइवान एक आंतरिक मुद्दा है और यह चीनी लोगों का मामला है। उन्होंने बीजिंग में कहा, "हम अमेरिका द्वारा चीन के ताइवान क्षेत्र के साथ किसी भी प्रकार के सैन्य संबंध बनाने का कड़ा विरोध करते हैं, और अमेरिका द्वारा चीन के ताइवान क्षेत्र को हथियार बेचने का भी कड़ा विरोध करते हैं। यह स्थिति सुसंमत और स्पष्ट है।" झांग ने आगे कहा कि ताइवान "चीन के मूल हितों का केंद्र" है, और अमेरिका के पिछले प्रशासनों द्वारा किए गए वादों का सम्मान करना "अंतरराष्ट्रीय दायित्व है जिन्हें पूरा करने के लिए अमेरिकी पक्ष कर्तव्यबद्ध है।" वाशिंगटन की "एक

चीन" नीति के तहत अमेरिका आधिकारिक तौर पर ताइवान की संप्रभुता पर कोई रुख नहीं अपनाता है, लेकिन बीजिंग के इस रुख को स्वीकार किए बिना मानता है कि यह ट्रंप चीन का है। ताइवान चीन का एक हिस्सा है, जो न कभी कोई देश रहा है और न कभी बनगा। ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करने का हमारा संकल्प चट्टान की तरह मजबूत है और ताइवान की स्वतंत्रता को कुचलने की हमारी क्षमता अटूट है। ट्रंप चीन की यात्रा पर ऐसे समय में जा रहे हैं जब ताइवान की विपक्षी-नियंत्रित संसद ने राष्ट्रपति लाई चिंग-ते द्वारा मांगे गए 40 अरब डॉलर के विशेष रक्षा बजट के केवल दो-तिहाई हिस्से को ही मंजूरी दी है। इस बजट का उपयोग अमेरिकी हथियारों की खरीद के लिए किया जाएगा, लेकिन ड्रोन जैसे घरेलू कार्यक्रमों में कटौती की गई है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने रविवार को कहा कि अमेरिका इस बात से निराश है कि रक्षा खर्च को जितनी राशि की मंजूरी मिली है, वह वाशिंगटन के अनुसार आवश्यक राशि से कम है। ताइवान पर ट्रंप से मोलभाव करेगा चीन ताइवान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि ताइपे के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि बीजिंग इस काम किए गए बजट का इस्तेमाल ट्रंप के साथ मोलभाव करने के लिए एक हथियार के तौर पर कर सकता है। अधिकारी ने आगे कहा, "चीन यह तर्क दे सकता है कि ताइवान की विधायिका हथियारों की खरीद का विरोध करती है और अमेरिका को ताइवान के लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए - ताकि राष्ट्रपति ट्रंप को ताइवान के लिए रक्षा सहायता रोकने या कम करने के लिए मनाया जा सके।"



# पाकिस्तान की धोखेबाजी का पर्दाफाश, सालों से ईरानी मिलिट्री जेट्स को दे रहा था पनाह, अमेरिका हैरान

एजेंसी इस्लामाबाद

अमेरिका और ईरान में मध्यस्थ बने पाकिस्तान की पोल खुल गई है। वह अमेरिका और ईरान दोनों से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हाल में ही अमेरिकी मीडिया ने बताया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और इजरायल के हमलों से बचाने के लिए ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर पनाह दी थी। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान लंबे समय से ईरानी सैन्य विमानों को शरण दे रहा है। उसने न सिर्फ मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के दौरान, बल्कि किसी भी दूसरे संघर्ष में ईरानी लड़ाकू विमानों की मेजबानी की है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2025 के एक यूट्यूब वीडियो में दिखा है कि कराची एयरपोर्ट के रनवे पर ईरानी ट्रांसपोर्ट और हवाई रिपयूलिंग टैंकर खड़े हैं। यह घटना इजरायल के

'ऑपरेशन राइजिंग लायन' खत्म होने के कुछ हफ्तों बाद की है। इस दौरान इजरायल ने ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर जबरदस्त हवाई हमले किए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह वीडियो CBS News की उस रिपोर्ट के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान इस समय ईरानी विमानों को पनाह दे रहा है। इससे पाकिस्तान की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि, पाकिस्तान ने इन दावों को फर्जी बताया है। उसका कहना है कि ईरानी विमान अमेरिका के साथ वार्ता के पहले राउंड में शामिल होने के लिए उनके देश पहुंचा था। CBS News की रिपोर्ट में बताया गया था कि 25 अप्रैल को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ईरानी वायुसेना के RC-130H Khofash विमान को देखा गया था। इसकी एक हाई-रिजॉल्यूशन सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई थी।

RC-130H, ईरान द्वारा दशकों से इस्तेमाल किए जा रहे मशहूर C-130 'हरक्यूलिस' विमान का एक खास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है। ईरान इसका इस्तेमाल जासूसी और टोही मिशन के लिए करता है। Intel Lab के शोधकर्ता डेमियन साहमन ने बताया कि यह विमान 11 और 12 अप्रैल 2026 के बीच नूर खान एयरबेस पर पहुंचा था और कम से कम 12 मई 2026 तक, यानी अपने आगमन के लगभग एक महीने बाद तक, वहीं जमीन पर खड़ा रहा। इस पूरे समय के दौरान यह विमान उसी जगह पर खड़ा रहा। सीनेट हाउस एग्जिप्रिएशन्स कमेटी की सुनवाई को संबोधित करते हुए, अमेरिकी सीनेटर ग्राहम ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टॉफ के चेयरमैन जनरल डैन केन से कहा कि उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है।





ताप्ती नदी उद्गम पर मिला प्राचीन गोमुख

सफाई अभियान में ऐतिहासिक जल संरचनाएं मिलीं, संरक्षण की मांग

दैनिक कारखाने का सफर। बैतूल

ताप्ती नदी के उद्गम स्थल पर सामाजिक कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं द्वारा चलाए गए एक व्यापक सफाई अभियान के दौरान एक प्राचीन गोमुख और कई ऐतिहासिक जल प्रवाह संरचनाएं सामने आई हैं। इस खोज ने क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। सफाई अभियान के दौरान मां ताप्ती के इस प्राचीन गोमुख को साफ किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि ताप्ती नदी का मूल प्रवाह इसी गोमुख से निकलता है और एक छोटे सरोवर से होकर नदी का रूप लेता है। निरीक्षण में गोमुख के आसपास प्राचीन नक्काशीदार पत्थर और पुरानी संरचनाएं मिली हैं, जो इसकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करती हैं। अभियान में शामिल लोगों दिनेश कालभोर, गोलू उघड़े ने बताया कि गोमुख के पास लगभग 8 फीट गहरी एक नहरनुमा संरचना भी मिली है। यह प्राचीन जल निकासी व्यवस्था और स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में 'सुलोज गेट' कहे जाने वाले हिस्से को भी प्राचीन गोमुख व्यवस्था का ही एक भाग बताया गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि प्राचीन गोमुख की वास्तविक पहचान को मिटाकर उसे नई पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने छोटे सरोवर क्षेत्र में मौजूद प्राचीन स्तंभों को तोड़कर अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि इतनी महत्वपूर्ण धरोहर को नुकसान पहुंचाए जाने के बावजूद संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, प्राचीन संरचनाओं का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण और धरोहर को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि मां ताप्ती करोड़ों लोगों की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए, उद्गम स्थल की ऐतिहासिक पहचान और प्राचीन संरचनाओं का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।



बैतूल में दस साल बाद कोर्ट ने शादी शून्य की आमला कोर्ट का फैसला, महिला का पहले से था विवाह, तलाक के दस्तावेज नहीं मिले

दैनिक कारखाने का सफर। बैतूल

बैतूल जिले के आमला स्थित जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एक अहम फैसले में 13 अगस्त 2015 को हुए विवाह को शून्य घोषित कर दिया। अदालत ने माना कि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-5 के प्रावधानों के विपरीत हुआ था, क्योंकि महिला का पहले से विवाह अस्तित्व में था और उसका वैधानिक तलाक नहीं हुआ था। न्यायालय ने पति की ओर से दायर याचिका स्वीकार करते हुए विवाह को प्रारंभ से ही अमान्य घोषित कर दिया। मामला आमला निवासी युवक द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2015 में उसका विवाह छिंदवाड़ा जिले की निवासी युवती से कराया गया था। बाद में उसे पता चला कि महिला का पूर्व विवाह वर्ष 2011 में हो चुका था और उसका कानूनी तलाक नहीं हुआ था। पति का आरोप था कि महिला और उसके परिजनों ने यह तथ्य छिपाकर शादी कराई। याचिकाकर्ता के अनुसार, शादी के बाद दोनों के बीच लगातार विवाद होते रहे। महिला ने दहेज प्रताड़ना और भ्रण-पौषण से जुड़े मामले भी दर्ज कराए थे। पति ने आरोप लगाया कि महिला उसके साथ रहना नहीं चाहती थी और लगातार विवाद करती थी। वर पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय के मुताबिक,



सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, दस्तावेज और शपथ पत्रों की जांच की। न्यायालय ने पाया कि नोटरी के समक्ष दिया गया शपथ पत्र हिंदू रीति-रिवाजों से संपन्न वैध विवाह का प्रमाण नहीं माना जा सकता। साथ ही महिला के पहले विवाह के समाप्त होने का कोई वैधानिक दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-11 के तहत ऐसा विवाह शून्य माना जाएगा। इसके आधार पर 13 अगस्त 2015 को हुआ विवाह निरस्त घोषित कर दिया गया। इस दंपती का एक 8 साल का बेटा भी है, जिसको कस्टडी को लेकर कोर्ट में अलग से मामला चल रहा है। फैसले के बाद याचिकाकर्ता को कानूनी राहत मिली है। इसे ऐसे मामलों में अहम माना जा रहा है, जहां पूर्व वैवाहिक स्थिति छिपाकर विवाह किए जाते हैं।

मुलताई में अवैध शराब बेचते 10 आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने 54.900 लीटर देशी शराब जब्त की, जारी रहेगा अभियान

दैनिक कारखाने का सफर। मुलताई

बैतूल जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मुलताई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बुधवार को अवैध शराब बेचते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से कुल 54.900 लीटर देशी शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 25,290 रुपये है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी और एसडीओपी एस.के. सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेंद्रसिंह परिहार के नेतृत्व में हुई। पुलिस टीम ने मुखबिरी की सूचना पर मुलताई कस्बा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। दबिश के दौरान, गिरफ्तार किए गए आरोपियों से शराब रखने और बेचने का वैध लाइसेंस मांगा



गया। हालांकि, कोई भी आरोपी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद, सभी के खिलाफ आवकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत अलग-अलग मामले दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कामथ निवासी पंकज पवार, मनीष अहिरवार, सतवंत साहू, इंदल

लबाड़े और सोनिया भूमरकर शामिल हैं। मुलताई निवासी रवि साहू, मनोज कुशवाह, हुकुमचंद साहू, निलेश खेरपारे और दिलीप बामने को भी पकड़ा गया। आरोपियों से 15 से लेकर 70 पाव तक देशी शराब जब्त की गई। सोनिया भूमरकर के पास से सर्वाधिक 70 पाव और दिलीप बामने के पास से

पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने पुलिस टीम को इस कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध शराब, जुआ, सट्टा और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आमजन से भी ऐसी गतिविधियों के संबंध में पुलिस को सूचना देने की अपील की है।

मुलताई में चना खरीदी केंद्र में अनियमितता: किसानों का चना अधिक तौला जा रहा था, समिति प्रबंधक निलंबित

दैनिक कारखाने का सफर। मुलताई

मुलताई के कृषि उपज मंडी समिति स्थित चना खरीदी केंद्र में बुधवार को अनियमितता सामने आई है। निर्यात मात्रा से अधिक चना तौले जाने की शिकायत देविदास नरवरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर हरीराम बोरबन को केंद्र का प्रभार सौंपा गया है। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर बैतूल सौरभ संजय सोनवने के निर्देश पर कार्रवाई की गई। अनुबिभागीय अधिकारी राजस्व राजीव कहरार के मार्गदर्शन में एक संयुक्त जांच दल का गठन किया गया, जिसमें तहसीलदार संजय बरेया, उपायुक्त सहकारिता के.के. शिव, सहायक संचालक कृषि सुरेंद्र पराते और जिला विपणन अधिकारी प्रदीप ग्रवाल शामिल थे। जांच दल ने चना खरीदी केंद्र प्रवेश द्वार पर और जिला विपणन अधिकारी प्रदीप ग्रवाल द्वारा निर्यात तौल सीमा से अधिक मात्रा में चने की तुलाई की जा रही थी। मौके पर ही पंचनामा तैयार कर शिकायत की पुष्टि की गई। जांच रिपोर्ट



के आधार पर समिति प्रबंधक देविदास नरवरे को तत्काल निलंबित कर दिया गया। उनका मुख्यालय संस्था कार्यालय निर्यात किया गया है। खरीदी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए हरीराम बोरबन, जो विक्रेता एवं प्रभारी सहायक प्रबंधक हैं, को केंद्र का नया प्रभार सौंपा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों के हितों की सुरक्षा और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। भविष्य में भी शिकायत मिलने पर त्वरित जांच और कार्रवाई जारी रहेगी।

भारत लल्ली चौक रोटरी में गड़बड़ी, हाईमास्ट के पास अतिक्रमण मिला नगरपालिका अफसरों ने किया निरीक्षण; इंदिरा कन्या विद्यालय भवन कंडम घोषित होगा

दैनिक कारखाने का सफर। बैतूल

बैतूल में शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नगरपालिका ने व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बैतूल विधायक के निर्देश पर शुरू किए गए इस अभियान में गंज क्षेत्र में बनाए गए डिवाइडर और लल्ली चौक रोटरी में कई खामियां सामने आईं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) नवनीत पांडे के नेतृत्व में अधिकारियों ने शहर के प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण, साफ-सफाई, सार्वजनिक निर्माण कार्यों और जर्जर भवनों की स्थिति की समीक्षा की गई। लल्ली चौक रोटरी में मिला गलत अलाइनमेंट निरीक्षण के दौरान लल्ली चौक स्थित रोटरी में निर्माण करने को कहा गया। साथ ही लल्ली चौक



पाया गया। अधिकारियों ने तत्काल सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए। हाईमास्ट पोल के आसपास अतिक्रमण मिलने पर उसे हटाने और व्यवस्थित करने की कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही लल्ली चौक के सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही गई। इंदिरा कन्या विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति का भी निरीक्षण किया गया। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए

वैकल्पिक व्यवस्था करने और भवन को कंडम घोषित कराने के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए। गंज क्षेत्र में एचडीएफसी बैंक के सामने बनाए गए डिवाइडर की गुणवत्ता जांच में निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद संबंधित ठेकेदार को सुधार कार्य करने के निर्देश दिए गए। शहर के अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी साफ-सफाई और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर नियमित निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। नगरपालिका शांति कॉम्प्लेक्स और दुकानों के निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण और अव्यवस्था मिलने पर कार्रवाई करने को कहा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नगरपालिका सुविधाओं और शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए इस तरह के निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे।

ट्रेन हादसे में घायल महिला 4 दिन से अस्पताल में परिजनों की तलाश जारी, खुद को लखनादौन का बता रही, पुलिस ने जारी किया नंबर

दैनिक कारखाने का सफर। बैतूल

बैतूल जिला अस्पताल में पिछले चार दिनों से एक अज्ञात महिला भर्ती है। उसे ट्रेन दुर्घटना के बाद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। महिला की पहचान अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन और जीआरपी पुलिस उसके परिजनों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार, महिला ने अपना नाम संध्या और पति का नाम पप्पू बताया है। उसने खुद को सिवनी जिले के लखनादौन क्षेत्र का निवासी बताया है। महिला की उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। जीआरपी बैतूल पुलिस चौकी प्रभारी रविश कुमार के अनुसार, महिला धाराखोह और मरामाड़िरी रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेक के पास घायल अवस्था में मिली



थी। वह वहां कैसे पहुंची और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस का मानना है कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत हो रही है, जिसके कारण उसके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि नहीं हो पा रही है। बताए

नंबर पर कॉल किया लेकिन पहचान नहीं हुई पुलिस ने महिला द्वारा बताए गए परिवार से संपर्क किया, जहां से जानकारी मिली कि वह पिछले करीब तीन साल से घर से बाहर है और संपर्क में नहीं है। इसके बाद उसकी पहचान की पुष्टि नहीं हो सकी। महिला 9 मई से जिला अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में भर्ती है और उसका इलाज जारी है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला के परिजनों तक सूचना पहुंचना जरूरी है ताकि उसे उचित देखभाल मिल सके। इस संबंध में संपर्क के लिए मोबाइल नंबर 6260832771 जारी किया गया है। पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कोई महिला को पहचानता हो या उसके परिवार की जानकारी रखता हो तो तुरंत संपर्क करें, ताकि उसे परिवार तक पहुंचाया जा सके।